RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 122
दि. 01.09.2025, सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

'अमित शाह का सिर काटकर', ये बयान देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ी मुश्किल, दर्ज हुई एफआईआर

छत्तीसगढ़ पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर रायपुर में रविवार को दर्ज की गई। मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में अमित शाह की कथित विफलता को लेकर कहा था कि "अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर दिया जाना चाहिए"।

इस टिप्पणी को लेकर कई भाजपा नेताओं ने मोइत्रा की आलोचना की है।

प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कजान में अपनी पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देश विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। भारत और चीन तथा उनके 2.8 अरब लोगों के बीच परस्पर सम्मान, आपसी हित और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर एक स्थिर संबंध और सहयोग दोनों देशों की वृद्धि और विकास के साथ-साथ 21वीं सदी के रुझानों के अनुरूप एक बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष सफल सैन्य वापसी और उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा संबंधित मुद्दों के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस महीने के आरंभ में दोनों विशेष प्रतिनिधियों द्वारा अपनी वार्ता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकार किया तथा उनके प्रयासों को और समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीजा की बहाली के आधार पर सीधी उड़ानों और वीजा सुविधा के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में, उन्होंने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक राजनीतिक और कार्यनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों एवं चुनौतियों पर साझा आधार का विस्तार करना आवश्यक समझा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में घाटलोडिया के आयुष्मान वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ

गांधीनगर, 31 अगस्त : अहमदाबाद के घाटलोडिया वॉर्ड में रविवार को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से ह्यएक पेड़ माँ के नामह्न अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया।

पेड़ पर्यावरण तथा वातावरण शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ह्यएक पेड़ माँ के नामह्न अभियान अंतर्गत माता के नाम पर एक पेड़ लगाने के संकल्प के साथ घनिष्ठ वृक्षारोपण अभियान में अहमदाबाद महानगर पालिका के घाटलोडिया वॉर्ड में स्थित आयुष्मान वन में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

इस अवसर पर अहमदाबाद की

महापौर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, उप महापौर श्री जतिन पटेल, अहमदाबाद मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी, विधायक श्री बाबूभाई पटेल, अहमदाबाद मनपा आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि सहित अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री ने म्यांमार के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यांमार के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पड़ोस प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद-प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सीमा व्यापार सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भावी परिदृश्य पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जारी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर संपर्क को प्रेरित करेगी, साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि म्यांमार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से संपन्न होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत म्यांमार के नेतृत्व वाली और म्यांमार के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण संवाद और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग है।

प्रधानमंत्री ने म्यांमार की विकासात्मक आवश्यकताओं में सहयोग के लिए भारत की तत्परता दोहराई।

मोहम्मद अजहरुद्दीन को एमएलसी के लिए किया गया नामित, क्रिकेटर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि उन्हें तेलंगाना कैबिनेट द्वारा राज्यपाल कोटे से विधान परिषद (MLC) सदस्य के रूप में नामित किए जाने पर गहरा सम्मान और विनम्रता महसूस हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और के.सी. वेणुगोपाल का आभार जताते हुए कहा कि वह उनके विश्वास और आशीर्वाद के लिए शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और तेलंगाना मामलों की एआईसीसी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का भी मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में डायल 112 के अंतर्गत जनरक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद, गुजरात में डायल 112 के अंतर्गत जनरक्षक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि '112 जनरक्षक' प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि '112 जनरक्षक' प्रोजेक्ट के लोकार्पण के साथ गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 217 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित आवासों और कार्यालयों का उद्घाटन और कुल 1000 पुलिस वाहनों का लोकार्पण भी किया गया है। श्री शाह ने कहा कि माणसा के पुलिस स्टेशन को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त होना उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि वे माणसा में ही जन्मे, बड़े हुए और वहीं से गुजरात तथा देश की राजनीति में योगदान देने के योग्य बने, इसलिए माणसा के पुलिस स्टेशन को बीआईएस प्रमाणन प्राप्त होना उनके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि '112' प्रोजेक्ट देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपातस्थिति में हर प्रकार की सुविधा समय पर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी पहल है।

श्री शाह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आज गुजरात 'डायल 112 जनरक्षक' के नक्शे में अपना स्थान दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न टोल-फ्री नंबरों का जाल, जैसे पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, फायर सर्विस के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098, आपदा के लिए 1070 और 1077, लोगों को भ्रमित कर रहा था। लेकिन लोगों को अब आपदा प्रबंधन, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, फायर सर्विस, एम्बुलेंस और पुलिस सहायता जैसी किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवा केवल एक नंबर, 112 डायल करने से बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से संचालित अत्यंत उन्नत नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) के माध्यम से सभी प्रकार की सेवाओं का समन्वय और जीपीएस से सुसज्जित वाहन एक वैज्ञानिक व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे।

शुरू हुई 'द बंगाल फाइल्स' की एडवांस बुकिंग, विवेक अग्निहोत्री ने किया ऐलान

विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का क्लैश 'बागी 4' से हो रहा है। विवेक की ये फिल्म 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की दर्दनाक पृष्ठभूमि पर बनी है।

ये फिल्म, उनके मुताबिक सच दिखाने वाली ट्रिलॉजी का आखिरी चैप्टर है। इसमें द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में शामिल हैं। जो पहले ही रिलीज हो चुकी हैं। द बंगाल फाइल्स का टीजर को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है।

फिल्म रिलीज होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। इसके पहले ही विवेक ने फिल्म की एडवांस बुकिंग खोल दी है।

"गर्व से स्वदेशी की भावनाहमें फिट रहने और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी तरीकों को अपनाने के लिए अवश्य प्रेरित करेगी" - डॉ. मनसुख मांडविया

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय राजधानी आज सुबह उस समय जीवंत हो उठी, जब प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष संस्करण का आयोजन किया गया।इसका नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने किया। यह कार्यक्रम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित तीन दिवसीय अखिल भारतीय खेल उत्सव के समापन दिवस का हिस्सा था।

डॉ. मांडविया ने साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और इसे एक ऐसा आंदोलन बताया जो "भारतीयों को उनकी धरती से जोड़ता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करता है।" उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा: "तीन दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल गया है। गांव के खेल के मैदानों से लेकर राष्ट्रीय स्टेडियमों तक, लगभग 30 करोड़ भारतीयों ने खेल, फिटनेस और मेजर ध्यानचंद जी की विरासत का उत्सव मनाया है। यह अभूतपूर्व भागीदारी भारत की बढ़ती खेल संस्कृति और फिटनेस को जीवन का एक हिस्सा बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प को दशार्ती है।"

उन्होंने कहा, "साइकिल चलाना सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का माध्यम है। इस तरह की सरल और टिकाऊ कार्य प्रणलियां हमारी आत्मनिर्भरता और जो हमारा है, उस पर गर्व करने के हमारे आदर्शों को दशार्ती हैं। गर्व से स्वदेशी की यह भावना हमें स्वस्थ और मजबूत रहने के स्वदेशी तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी भारत का निर्माण भी करती है।"

इस पहल का राष्ट्रव्यापी स्तर अभूतपूर्व रहा। 700 जिलों के 10,000 से अधिक स्थानों पर, लगभग 30 करोड़ नागरिकों ने खेल के मैदानों केकार्यकलापों, साइकिलिंग रैलियों और स्वदेशी खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

देश के विभिन्न हिस्सों से 3,000 से अधिक नमो फिट इंडिया क्लब साइक्लिंग भी इसमें शामिल हुए।

बिहार वोटर लिस्ट पर कांग्रेस का बड़ा आरोप: 89 लाख शिकायतें दीं, लेकिन सब खारिज हुई, ईडी ने क्या दिया जवाब?

(जीएनएस)।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (रस्रीं' क्ल्लशील्ल२५ी फी५२ङ्गल्ल -रक्फ) को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग (एउ) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने वोटर लिस्ट से जुड़ी 89 लाख शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन आयोग ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया।

पवन खेड़ा ने कहा-"चुनाव आयोग बार-बार यह प्रचारित करता है कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई शिकायत नहीं आ रही। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने 89 लाख शिकायतें दाखिल कीं, लेकिन जब हमारे बूथ लेवल एजेंट्स (इछअ) उन्हें लेकर पहुंचे तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि शिकायतें सिर्फ व्यक्ति ही कर सकता है, राजनीतिक दल नहीं।"

कांग्रेस ने क्या-क्या लगाएं आरोप?

पवन खेड़ा के मुताबिक-चुनाव आयोग ने बिहार के 90,540 मतदान केंद्रों पर कुल 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इनमें से 25 लाख नाम प्रवासन की वजह से हटे। करीब 22 लाख मृतक मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। वहीं 9.7 लाख वोटर अपने पते पर अनुपस्थित पाए जाने के कारण लिस्ट से बाहर कर दिए गए।

कांग्रेस ने दावा किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, उनके लिए बीएलओ (इछड) ने शिकायतें और आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन आयोग ने एक भी शिकायत को स्वीकार नहीं किया।

कांग्रेस ने दिए चौंकाने वाले आंकड़े

कांग्रेस का दावा है कि 20,368 बूथ ऐसे हैं जहाँ 100 से ज्यादा नाम हटाए गए। 1,988 बूथों में 200 से अधिक नाम काटे गए। 7,613 बूथों पर 70% से अधिक महिलाओं के नाम डिलीट किए गए। 635 बूथों पर माइग्रेंट श्रेणी में हटाए गए नामों में 75% से ज्यादा महिलाएं हैं।

कई मामलों में एक ही वोटर को दो एढकउ कार्ड नंबर दिए गए। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास इन शिकायतों की रसीदें भी मौजूद हैं, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने मांग की कि एउ को घर-घर जाकर दोबारा जांच करनी चाहिए ताकि गलतियां सुधारी जा सकें।

चुनाव आयोग का जवाब

कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा-"आज तक बिहार में कांग्रेस के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BLA ने न तो कोई दावा और न ही आपत्ति तय प्रारूप में दाखिल की है।"

सम्पादकीय

एससीओ के दौरान पीएम की कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की संभावना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो दिवसीय जापान की सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न करके शनिवार को चीन पहुंच गए जहां उन्हें रविवार व सोमवार को दिन 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है और इस बैठक के इतर चीन, रूस एवं ईरान के साथ ही कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की संभावना है। इस बैठक में हिस्सा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को भी लेना है कितु उनसे तो यदि दुआसलाम हो जाए तब भी बहुत बड़ी खबर बन सकती है। इस बार की एससीओ बैठक निश्चित रूप से बहुचर्चित होने वाली है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने को अमेरिका ने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया है। अमेरिका एससीओ से भी उतना ही भड़क रहा है जितना कि वह ब्रिक्स से खौफ खाता है।

असल में एससीओ की शुरूआत 1996 में शंघाई फाइव के रूप में हुई थी जिससे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और तजाकिस्तान शामिल थे। उस वक्त इस संगठन का उद्देश्य था कि शीत युद्ध के बाद सीमा विवादों को सुगमता एवं समझदारी से निपटाना। 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद इस संगठन का नाम शंघाई सहयोग संगठन हो गया। 2017 में भारत व पाकिस्तान तथा 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस के सदस्य बनने के बाद इसके स्वरूप में व्यापक विस्तार हुआ। यही नहीं इस संगठन में डायलाग पार्टनर के रूप में सउदी अरब, मिश्र, तुर्की, म्यांमार, श्रीलंका और कम्बोडिया जैसे 14 देशों को शामिल करके दुनिया के बनते-बिगड़ते समीकरणों में सक्षम बनाने के लिए एससीओ का और बड़ा स्वरूप बनाया गया। एससीओ के इस विस्तार से अमेरिका और यूरोप के देशों की आशंका स्वाभाविक है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ अनावश्यक टैरिफ से जोड़कर देख रहा है। यह सच है कि जून में जिस तरह राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू को पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच सहयोग, विश्वास और व्यवसाय बढ़ाने पर जोर दिया और उसके बाद विदेश मंत्री और एनएसए को भेज कर चीन के आशय को समझने की कोशिश गई, वह इस तथ्य का परिचायक है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया है कि ट्रंप प्रशासन पर भरोसा करना आत्मघात साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी यह भी जानते हैं कि चीन विश्वसनीय नहीं है, कितु वह यह भी जानते हैं ट्रंप के झूठ और दबंगई से भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में अस्थिरता आना निश्चित है, इसीलिए भारत की तरफ से चीन के साथ जब संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमति बन गई तभी चीन के विदेश मंत्रालय और भारत में चीन के राजदूत ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्लस 25 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने को गलत और अन्यायपूर्ण बताकर वाशिंगटन डीसी को यह संकेत दे दिया कि उसे भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने और सहयोग बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच चीन के विदेश मंत्री ने भारत में आकर भारत के लिए प्रतिबंधित दुर्लभ मृदा उर्वरक और सुरंग खोदने की मशीन देने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने 25 प्रतिशत टैरिफ यह कहकर भारत पर ठोंक दिया कि भारत द्वारा रूस से तेल लिया जाता है और उसी पैसे से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। अब देखने की बात तो यह है कि एक तरफ चीन भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है जबकि दूसरी तरफ ट्रंप और उनके सलाहाकार भारत पर इस तरह दुराशय के वशीभूत होकर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली और वाशिंगटन डीसी से संबंध एक बार फिर तीस साल पुरानी स्थिति में यानि न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए ट्रंप आमादा हैं। लेकिन चीन से संबंध सुधारने के लिए भारत पर दोषारोपण भी करते हैं। ट्रंप के व्यापार सलाहाकार पीटर नवारी तो यहां तक कहते हैं कि जिस चीन ने भारत के अक्साई चिन और लद्दाख के बड़े भू-भाग पर बलपूर्वक कब्जा कर रखा है, उसे देखते हुए भारत को चीन से सहयोग बढ़ाना हैरानी की बात है। चीन से बढ़ते संबंधों को लेकर अमेरिका की बैचेनी पर भारत को किसी तरह की संवेदनशीलता नजर नहीं आती क्योंकि भारत अब किसी के सलाह पर अपनी विदेश, व्यापार और रक्षा नीति का निर्धारण नहीं करता कितु भारत उतना जरूर जानता और समझता है कि मित्रता की आड़ में राष्ट्रीय हितों पर आघात करने वाले से अच्छा वह शत्रु है जो खुलेआम लड़ता है और दोनों के कामन शत्रुता का सामना करने के लिए एकजुटता के लिए सहमति व्यक्त करता है।

सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर संचालित जीपीएस सुविधा से युक्त वाहनों द्वारा गुजरात ने न्यू एज स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 31 अगस्त : राज्य में होने वाली आपराधिक घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य घटनाओं के समय आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों को पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नूतन दृष्टिकोण दिखाया है।

केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के निदेर्शानुसार राज्य के गृह विभाग द्वारा डायल 112 जनरक्षक प्रोजेक्ट तथा गुजरात पुलिस के नवनिर्मित आवासों एवं पुलिस वाहनों का केन्द्रीय गृह मंत्री तथा गांधीनगर के सांसद श्री अमित शाह ने रविवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में शुभारंभ-लोकार्पण किया।

गांधीनगर से प्रारंभ तथा लोकार्पित की गई इन विभिन्न सुरक्षा परियोजनाओं में डायल 112 जनरक्षक प्रोजेक्ट अंतर्गत अत्याधुनिक कॉल सेंटर तथा 500 जनरक्षक वैन का प्रस्थान और पुलिस के मोबिलिटी इम्प्रूमेंट प्रोग्राम अंतर्गत लगभग 534 नए बोलेरो वैन का लोकसेवा के लिए प्रस्थान-लोकार्पण शामिल हैं।

इस अवसर पर महानुभावों के करकमलों से पुलिस विभाग के चालकों को वाहनों की चाबी सांकेतिक रूप से सौंपी गई।

इसके अलावा गुजरात पुलिस आवास निगम द्वारा गृह विभाग के 217 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय तथा अनावासीय भवनों का भी श्री अमित शाह के करकमलों से लोकार्पण तथा देश में पहली बार गांधीनगर के माणसा पुलिस स्टेशन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया गया आईएस-157000 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जनरक्षक 112 का लोकार्पण करते हुए कहा कि अब आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर डायल करने से मुक्ति मिलेगी। केवल एक ही नंबर 112 डायल करने से पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन सबके लिए तत्काल मदद मिलेगी। सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर संचालित जीपीएस सुविधा से युक्त इन वाहनों द्वारा गुजरात सरकार ने न्यू एज स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जनरक्षक 112 के आधुनिक टेक्नोलॉजी से सज्ज कंट्रोल रूम से अहमदाबाद में 150 कर्मचारी 24 घण्टे 7 दिन सेवा देंगे और राज्य के नागरिकों को सेवा प्रदान करेंगे।

गुजरात की सुरक्षा के नूतन एवं महत्वपूर्ण कदमों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की जोड़ी की प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि गुजरात देश के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र वाला राज्य है। गुजरात का समुद्री किनारा, कच्छ या बनासकाँठा की सीमाओं पर पूर्व में अनेक अप्रिय घटनाएँ घटती थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में गुजरात की सीमाएँ अभेद्य दुर्ग समान बनी हैं। आज गुजरात कानून-व्यवस्था में नंबर वन है।

उन्होंने जोड़ा कि सुशासन से प्रेरित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद आतंकवाद, नक्सलवाद तथा घुसपैठ सहित सभी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। गुजरात में आज नारकोटिक्स, आतंकवाद, साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही कर नागरिकों की सुरक्षा तथा उन्हें तत्काल सेवाएँ पहुँचाने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में श्री पटेल तथा श्री संघवी ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

श्री शाह ने इस अवसर पर 217 करोड़ रुपए की लागत से जेल, होमगार्ड के कर्मचारियों के लिए आवासीय-अनावासीय मकानों का ई-लोकार्पण करते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारियों से किया गया वादा प्रधानमंत्री ने भली-भाँति निभाया है। प्रधानमंत्री के 11 वर्ष के कार्यकाल में यह स्थापित हुआ कि समग्र विश्व में भारत की सीमा व सेना से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। भारत आत्मरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाकर सीमाओं की रक्षा करने को सज्ज है।

आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के फलस्वरूप पूर्वोत्तर में 10 हजार से अधिक लोग सरेंडर हुए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 31 मार्च, 2026 को समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ह्यएक नंबर, अनेक सेवा काह्न डायल 112 के जनरक्षक प्रोजेक्ट को राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए सरकार का विजनरी कदम बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा शक्ति को अधिक सुदृढ़ बनाकर टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग राज्य के पुलिस बल में हो रहा है। यह समारोह भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से नागरिकों की सेवा व सुरक्षा के ध्येय को साकार करने वाला कार्यक्रम है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री व केन्द्रीय गृह मंत्री ने राज्य पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के साथ आतंकवाद, अपराध तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई है। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशिक्षण की पूरी तासीर बदल कर नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को आधुनिकता के साथ स्मार्ट पुलिसिंग के लिए अधिकाधिक सज्ज व सक्षम बनाया है। हमारे पुलिस जवान इंटेलिजेंस, सर्वेलांस तथा कन्विक्शन के लिए समयानुसार बदलाव लाकर स्ट्रीट स्पेस से लेकर साइबर स्पेस तक अपराध नियंत्रण हेतु कैपेबल हैं।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पुलिस के टेक्नोसेवी जवान स्वदेशी टेक्नोलॉजी विकसित कर स्मार्ट, सेफ तथा सेक्योर गुजरात से विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात बनाएंगे।

गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी ने आज के दिन को गुजरात की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आज से अब राज्य के नागरिकों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 100, 108, 101, 181, 1098, 1070-1077 आदि याद नहीं रखने पड़ेंगे। इन सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। नागरिकों को यह नंबर डायल करने से त्वरित मदद के लिए जरूरी टीम भेजने का कार्य होगा। सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एकीकृत नंबर 112 की लॉन्चिंग से आपातकालीन सेवाएँ और सुदृढ़ एवं प्रभावी बनेंगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उनकी अध्यक्षता में छह माह पहले आयोजित हुई वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में आपातकालीन सेवाओं के एकीकरण, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम घटाने तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया था। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में टेक्नोलॉजी से युक्त फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल बढ़ाने के साथ केवल छह माह में ही सभी आपातकालीन सेवाओं को एक छत्र तले लाने का यह भगीरथ कार्य आज पूरा किया है।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से लोगों को त्वरित व प्रभावी रिस्पॉन्स मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि जनरक्षक वाहनों को कोई पुलिस थाने की सीमा बाधित नहीं करेगी। घटनास्थल के सबसे निकट जो वाहन होगा, वह सबसे पहले पहुँचेगा। कॉल करने वाले की सटीक लोकेशन प्राप्त कर इमर्जेंसीसेवा की टीमों का तुरंत प्रस्थान हो सकेगा। इन सेवाओं में टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग किया गया है।

वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में श्री शाह द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार गुजरात में डेडिकेटेड सेंटर फॉर साइबर एक्सीलेंस तैयार करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उनके द्वारा राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को हम मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण गुजरात सबसे सुरक्षित राज्यों में एक है। गुजरात में अपराध दर उल्लेखनीय रूप से घटी है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत व राजकोट देश के सुरक्षित शहरों में शामिल हैं। आज 112 प्रोजेक्ट अंतर्गत 500 वाहन और अन्य 534 वाहन गुजरात पुलिस को मिलने से गुजरात और सुरक्षित बनेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए वाहन तथा एआई की मदद से रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी।

श्री दास ने जोड़ा कि केन्द्र द्वारा तैयार किए गए तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन में गुजरात देश में अग्रसर है।

इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, राज्य पुलिस महानिदेशक व मुख्य पुलिस अधिकारी श्री विकास सहाय, विधायक सर्वश्री रीटाबेन पटेल, अल्पेश ठाकोर, जे. एस. पटेल, लक्ष्मणजी ठाकोर, बलराजसिंह चौहाण, गृह विभाग की प्रधान सचिव श्री निपुणा तोरवणे, ईएमआरआई निदेशक श्री के. कृष्णम राजू सहित राज्यभर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मनपा पार्षद तथा बड़ी संख्या में नगरजन उपस्थित रहे।

श्रेया घोषाल ने बताई अपनी कहानी, संजय लीला भंसाली की ये फिल्म बनी उनके करियर की टर्निंग पॉइंट

(जीएनएस)।

संजय लीला भंसाली इंडस्ट्री के जाने-माने फिल्ममेकर हैं। इसके अलावा संजय को लोग उनके म्यूजिक के लिए भी पहचानते हैं। हाल ही में सिंगर श्रेया घोषाल ने बताया कि फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली ने उन्हें पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें भंसाली के साथ काम करने के लिए बहुत धैर्य और विश्वास की जरूरत थी, उन्होंने अपनी पहली फिल्म देवदास (2002) को भी याद किया।

श्रेया घोषाल ने कहा, "अब सच ये था कि संजय जी की फिल्म में एक नई लड़की गा रही है, ये खबर वायरल हो गई थी। बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया कि हमारा भी एक गाना है, लेकिन मैंने संजय जी को वर्ड देकर कहा था कि जब तक ये गाना रिलीज नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।"

उन्होंने आगे बताया, "तब मैं सिर्फ 16 साल की थी और ये फैसला असल में मेरे पापा ले रहे थे, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी और अपना काम कर रही थी। इतनी सारी ऑफर्स आने के बावजूद, गाना रिलीज होने से पहले ही, उन्हें ठुकराना आसान नहीं था। लेकिन हमने अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का फैसला किया और वही सही लगा।"

श्रेया घोषाल ने बताया कि देवदास के रिलीज से पहले उन्होंने कई ऑफर्स ठुकरा दिए थे। उनका मानना है कि यही फैसला उनकी जगह फिल्म में पक्की करने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा, "ये काम कर गया, अगर मैं उन सबके लिए गा देती तो शायद देवदास में नहीं होती, मुझे पूरा यकीन है। संजय जी इस बात को लेकर बहुत साफ थे कि वही मुझे लॉन्च करेंगे और मुझे फिल्म रिलीज तक सब्र रखना होगा।"

प्रोजेक्ट्स की बात करें तो संजय लीला भंसाली अब अपनी अगली बड़ी फिल्म लव एंड वॉर का निर्देशन करते दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि इस फिल्म को अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है।

नकली चांदी खरीदने से बचना है? आज से सिल्वर ज्वैलरी पर भी हॉलमार्किंग, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

(जीएनएस)।

भारत सरकार अब चांदी के गहनों पर भी सोने की तरह शुद्धता की गारंटी देने जा रही है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से नया हॉलमार्किंग नियम लागू होगा। हालांकि शुरूआत में हॉलमार्किंग सिस्टम वाला नियम अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक रहेगा। यानी ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार हॉलमार्क वाली चांदी या बिना हॉलमार्क वाली चांदी खरीद सकेंगे।

क्या है नया नियम?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने चांदी की शुद्धता के लिए सिल्वर ज्वेलरी के लिए 6 ग्रेड तय किए हैं - 800, 835, 900, 925, 970 और 990। हर ज्वेलरी पर एक 6 अंकों का Hallmark Unique Identification Number (HUID) होगा। यह सिस्टम पुराने हॉलमार्किंग तरीकों को पूरी तरह बदल देगा।

हॉलमार्किंग क्यों जरूरी है?

हॉलमार्किंग का मतलब होता है

गहनों में मेटल की शुद्धता का सरकारी प्रमाण। इक्र की लैब में टेस्टिंग के बाद ज्वेलरी पर निशान (Mark) लगाया जाता है। इससे ग्राहक को भरोसा मिलता है कि जिस चांदी के लिए वह पैसे दे रहा है, वही क्वालिटी उसे मिल रही है।

बिना हॉलमार्क वाले गहनों में मिलावट की संभावना ज्यादा रहती है।

अब हर गहने पर ल्वक्क नंबर होगा जिसे ग्राहक आसानी से BIS COre App पर जाकर Verify HUID फीचर से चेक कर सकता है।

ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा?

नकली और मिलावटी चांदी खरीदने से बचाव।

गहनों की शुद्धता पर पूरी तरह भरोसा।

मोबाइल ऐप से तुरंत जांचने की सुविधा।

ज्वेलरी मार्केट में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी।

1 सितंबर के बाद क्या बदलेगा?

सरकार ने साल 2021 में सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य की थी। उसी तर्ज पर अब चांदी पर भी नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। ग्राहक के पास विकल्प रहेगा कि वह हॉलमार्क वाली चांदी खरीदे या बिना हॉलमार्क वाली।

लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ेगी, लोग केवल हॉलमार्क वाली चांदी पर भरोसा करेंगे। इससे न सिर्फ ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि ज्वेलरी मार्केट से नकली और मिलावटी चांदी लगभग खत्म हो जाएगी।

"राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" विषय पर दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष मंत्रालय 'राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण' पर विभागीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव 3 और 4 सितंबर 2025 को, नई दिल्ली में सरिता विहार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में आयोजित 'राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण' पर विभागीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

राष्ट्रीय आयुष मिशन को मजबूत करने, राज्यों की क्षमता बढ़ाने और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा

आयुष शिखर सम्मेलन में छह विषयगत उप-समूह वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर चर्चा करेंगे

शिखर सम्मेलन में वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ आयुष एकीकरण और क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श करेंगे

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" विषय पर दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव करेंगे।

आगामी शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट टिप्पणियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिसमें जमीनी स्तर के सुझाव भी शामिल हैं। इस तरह के सहभागी दृष्टिकोण का उद्देश्य राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को मजबूत और महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना है। यह एक प्रमुख कार्यक्रम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी प्रणालियों को एकीकृत करके समग्र स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है।

आगामी शिखर सम्मेलन, 2025 में चौथे मुख्य सचिवों के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विशेष ध्यान दिए गए छह विषयगत शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का अंतिम आयोजन है। वर्ष भर आयोजित होने वाले ये शिखर सम्मेलन, केंद्र सरकार और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को प्रमुख विषयों पर केंद्रित विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कनिष्ठ अधिकारियों सहित सभी स्तरों पर भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, नीति आयोग ने शिखर सम्मेलनों के लिए छह विषयगत क्षेत्रों की पहचान की। "राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण" को छठे और अंतिम विषय के रूप में चुना गया, जिसमें आयुष मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नामित किया गया, जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है।

नीति आयोग के निर्देशों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुकूलन सत्रों और संकल्पना टिप्पणी (दिनांक 6 मई 2025) के प्रसार सहित व्यापक तैयारी गतिविधियाँ शुरू की हैं।

केंद्रित संवाद को सुगम बनाने के लिए, छह विषयगत उप-समूह गठित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जिसमें 6-7 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। कार्य समूह राज्यों और समन्वय के लिए प्रमुख नोडल राज्यों के साथ उप-विषय इस प्रकार हैः

वित्तीय प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन, परियोजना प्रबंधनः राजस्थान, मिजोरम, मेघालय, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। नोडल राज्यः राजस्थान और मिजोरम।

संगठनात्मक संरचना समीक्षा, जिसमें मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण शामिल हैः मध्य प्रदेश, सिक्किम, गोवा, बिहार, दिल्ली, नागालैंड। नोडल राज्यः मध्य प्रदेश और सिक्किम।

आयुष का आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकरण, जिसमें जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैंः छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, ओडिशा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। नोडल राज्यः छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश।

आयुष सुविधाओं के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ, जिनमें बुनियादी ढाँचा, आईपीएचएस आयुष मानक, स्वास्थ्य सेवा वितरण शामिल हैंः उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर। नोडल राज्यः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।

आयुष चिकित्सा और इसकी खरीद प्रणाली का गुणवत्ता आश्वासन, जिसमें ब्रांडिंग और पैकेजिंग शामिल हैः कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, पुद्दुचेरी, असम। नोडल राज्यः कर्नाटक और असम।

विभिन्न क्षेत्रों में आईटी-सक्षम डिजिटल सेवाएँः आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दमण और दीव, केरल। नोडल राज्यः केरल और महाराष्ट्र।

इस शिखर सम्मेलन में देश भर के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, महानिदेशकों, मिशन निदेशकों और आयुष आयुक्तों जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित रहने की संभावना है। आयुर्वेद, अनुसंधान, स्वास्थ्य नीति और डिजिटल शासन के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता वाले प्रख्यात विशेषज्ञों और पैनलिस्टों को सत्रों को समृद्ध बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञों की सूची में डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग, श्री जे.एल.एन शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य, डॉ. वी. एम. कटोच पूर्व महानिदेशक, आईसीएमआर, प्रो. भूषण पटवर्धन और कई अन्य शामिल हैं।

वित्तीय प्रबंधन और संगठनात्मक सुधार से लेकर गुणवत्ता आश्वासन और आईटी-सक्षम सेवाओं तक के क्षेत्रों को शामिल करते हुए, विषयों और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के समूहों को सावधानीपूर्वक रेखांकित किया गया है। प्रत्येक उप-विषय का समन्वय दो नोडल राज्यों द्वारा किया जाता है, जिससे केंद्रित और प्रभावी विचार-विमर्श सुनिश्चित होता है।

यह विभागीय शिखर सम्मेलन आयुष प्रणालियों को देश की स्वास्थ्य सेवा संरचना के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रोत्साहन देने, पहुँच, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह राष्ट्रीय आयुष मिशन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

रेल पटरी न करें पार, न पशुओं को भेजें रेलवे ट्रैक पर - हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पशुओं के रेलवे ट्रैक पर आने से रेल संचालन बाधित हुआ है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे ट्रैक के आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामिणों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्री दिनेश वर्मा (मंडल रेल प्रबंधक) के मार्गदर्शन में श्री मनीष मलिक (वरिष्ठ मंडल अभियंता/सम.) और श्री पी. एन. राय (मंडल सुरक्षा आयुक्त) के नेतृत्व में भावनगर मंडल के इंजीनियरिंग विभाग एवं रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के समीप रहने वाले नागरिकों को जागरूक कर सचेत किया जा रहा है।

अभियान के दौरान ग्रामीणों को :

1. रेल पटरी पार करने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं की जानकारी दी गई।

2. स्थानीय ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक के पास पशुओं को चराने से उत्पन्न खतरों और संभावित रेल दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया।

3. ग्रामीणों को यह भी आगाह किया गया कि यदि वे ऐसे कार्य करते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेल प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने एवं दूसरों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल पटरियों को पार न करें तथा पशुओं को भी रेलवे ट्रैक पर न जाने दें।

यात्रियों की सुविधा के लिए कब शुरू होंगी मुंबई में नई लोकल ट्रेनें, क्या बढ़ेगा किराया?

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चंद दिन पहले मुंबई के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक में विशेष रूप से मुंबई की उपनगरीय रेल सेवा में बदलाव किए गए हैं।

समिति ने पहले चरण में 268 वातानुकूलित (एसी) लोकल ट्रेनों की खरीद को मंजूरी दे दी थी। फडणवीस ने पहले ही मुंबईकरों के लिए बंद दरवाजों वाली लोकल ट्रेनों की घोषणा की थी। ये नई ट्रेनें मेट्रो जैसी आधुनिक होंगी और हाई क्वालिटी वाली सुविधाओं से लैस होंगी। आइए जानते हैं कब शुरू होंगी ये नई ट्रेनें?

कब शुरू होंगी मुंबई में नई लोकल ट्रेनें?

जानकारी के अनुसार, पहली नई ट्रेन नवंबर 2025 तक तैयार कर ली जाएगी, जिसे जनवरी 2026 से मुंबई में शुरू करने की योजना है। यह पहल विशेष रूप से गैर-वातानुकूलित (नॉन-एसी) ट्रेनों की सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसे मौजूदा 238 एसी ट्रेनों के बेड़े से अलग रखकर एक नई दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट था कि इन नई ट्रेनों के लिए टिकट दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। नई लोकल एसी ट्रेनों का किराए में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

पिछली कैबिनेट बैठक में केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और नागपुर के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठाणे से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 25 किलोमीटर लंबे उन्नत मार्ग के निर्माण को हरी झंडी मिली थी। इस प्रोजेक्ट से ठाणे, नवी मुंबई और मध्यवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों को तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

यह मार्ग औद्योगिक, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए बेहतर संपर्क प्रदान करेगा। पुणे में बढ़ती यातायात समस्या को भी इस निर्णय से राहत मिलेगी।

राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' खत्मः बिहार में महागठबंधन का नया खेल पलटेगी कांग्रेस? क्या होगी अगली चाल?

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना से नई दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मचाने वाली राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। सोमवार (01 सितंबर) यानी आज गांधी मैदान, पटना से बी.आर. अंबेडकर पार्क तक प्रतीकात्मक पैदल मार्च के साथ यह यात्रा औपचारिक रूप से खत्म होगी। इसके बाद राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।

पिछले दो हफ्तों में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव (राजद), दीपंकर भट्टाचार्य (सीपीआई-एमएल) और मुकेश सहनी (विकासशील इंसान पार्टी) के साथ मिलकर 1300 किमी की दूरी तय की, जिसमें 25 जिले और 110 विधानसभा सीटें कवर की गईं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस यात्रा के खत्म होने के बाद कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी।

बिहार में क्यों निकाली गई थी वोट अधिकार यात्रा?

कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (रक्फ़) के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने यह 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "लोगों का सबसे बड़ा अधिकार वोट है। जब वह ही छिनने लगे तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। यह यात्रा जनता के दिलों में भरोसा जगाने और

बीजेपी-जेडीयू की साजिश को उजागर करने के लिए जरूरी थी।"

यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा गूंजा नारा था - "वोट चोर, गद्दी छोड़"। इसे जनता के बीच 'वन पर्सन, वन वोट' की लड़ाई के तौर पर पेश किया गया। राहुल गांधी का संदेश साफ था कि अगर वोट का अधिकार छिन गया तो धीरे-धीरे राशन, पेंशन, किसानों की सब्सिडी और बेरोजगारी भत्ता जैसे अधिकार भी छिन जाएंगे।

विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन

यात्रा के दौरान महागठबंधन की एकजुटता भी देखने को मिली। राहुल गांधी के साथ लगातार तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी नजर आए। DMK प्रमुख और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंच साझा किया।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी और अपने प्रतिनिधि भेजे। इसके बावजूद, यह यात्रा INDIA गठबंधन की एकता का प्रतीक बनकर उभरी।

कांग्रेस की रणनीति और भविष्य

बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। यात्रा ने बिहार में अपने कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस को महागठबंधन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद की है।

2020 के विधानसभा चुनाव में उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 पर जीत हासिल की, वोट शेयर महज 9.48% रहा। लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भीड़ जुटाकर और माहौल बनाकर यह संदेश दिया कि वह महागठबंधन में मजबूत दावेदार है।

अब कांग्रेस इस यात्रा को सीट शेयरिंग में दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस इस बार भी 70 से 75 सीट का दावा कर रही है। हालांकि राजद 55-55 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी घोषणा की है कि वह जल्द ही महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में भी मतदाता घोटाले का सबूत पेश करेंगे।

यात्रा ने कांग्रेस को चर्चा में ला दिया है और अपनी प्रासंगिकता फिर से स्थापित करने के लिए एक मंच दिया है। लेकिन असली कसौटी चुनाव होंगे। इसके लिए पार्टी को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना होगा। रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं पर ठोस नीतियां बनानी होंगी। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की थीम को आर्थिक संदेश में बदलना होगा।

राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' से सम्पबंधित प्रमुख बातें - बिहार में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने का आरोप लगा। इसे "लोकतंत्र और वोट के अधिकार पर हमला" बताते हुए कांग्रेस ने यह यात्रा शुरू की। यह यात्रा करीब 1300 किलोमीटर लंबी रही। इसमें 25 जिले और 110 विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव (राजद), दीपंकर भट्टाचार्य (सीपीआई-एमएल) और मुकेश सहनी (वीआईपी)

मुख्यमंत्री विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों के लिए कल्याणार्थ आयोजित 'विमुक्त जाति दिवस समारोह' में सम्मिलित हुए

लखनऊ : 31 अगस्त, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार प्रत्येक विमुक्त व घुमन्तू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जनजाति समुदाय के लोगों ने अलग-अलग कालखण्डां में देश पर होने वाले हमलों का प्रतिरोध करने लिए योद्धा के रूप में काम कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। परिस्थितिवश पलायन करने से घर-बार जब्त या नष्ट हो जाने के परिणामस्वरूप यह जनजातीय समुदाय घुमन्तू बन गए।

मुख्यमंत्री जी आज यहां विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों के कल्याणार्थ आयोजित ह्यविमुक्त जाति दिवस समारोहह्ल में बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। इसके पूर्व, मुख्यमंत्री जी ने विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों के कल्याण पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों के कल्याण पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सन् 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के पश्चात जब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को महसूस हुआ कि यह जनजातियां उन्हें लम्बे समय तक भारत पर शासन नहीं करने देंगी, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 बनाकर इन जनजातियों को प्रताड़ित किया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 की मंशा जनजातीय समुदाय को जन्म से अपराधी घोषित करने की थी। वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बावजूद वर्ष 1952 तक यह जनजातियां क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 से प्रताड़ित होती रहीं। 31 अगस्त, 1952 को बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर के प्रयासों से इन जनजातियों को इस एक्ट से मुक्ति प्राप्त हुई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त होने के पश्चात इन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विमुक्त व घुमन्तू जाति की उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश के 09 जनपदों में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें रामपुर, फरुर्खाबाद, सारनाथ व चन्दापुर (वाराणसी), लखनऊ, गोरखपुर, गोण्डा, दुद्धी (सोनभद्र) तथा हसनपुर (सुल्तानपुर) स्थित विद्यालय सम्मिलित हैं। इसके अलावा ईश्वर शरण आश्रम पद्धति विद्यालय, प्रयागराज तथा प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ अनुदान पर संचालित हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 101 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इन सभी विद्यालयों में विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा इन आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए भोजन, स्कूल ड्रेस, पुस्तकों आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ में 02 तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 01 छात्रावास संचालित है। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासां में भी विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। विमुक्त जातियों की आजीविका हेतु जनपद कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी तथा मुरादाबाद में एक ही स्थान पर निवास हेतु भूमि, कृषि योग्य भूमि का पट्टों पर आवंटन तथा विद्यालयों की स्थापना राजकीय उन्नयन बस्ती के नाम से की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों तथा कोरोना कालखण्ड में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए अत्याधुनिक अवसरंचना सुविधाओं से युक्त 18 अटल आवासीय विद्यालयां का निर्माण किया गया है। इन विद्यालयों में अब तक 18 हजार ऐसे बच्चों ने प्रवेश प्राप्त कर स्वयं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वनटांगिया ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा तथा इस समुदाय को मत देने का अधिकार दिया गया। वर्ष 2017 से पूर्व किसी भी वनटांगिया परिवार का पक्का मकान नहीं था। आज वनटांगिया समुदाय के परिवारों के लिए पक्के मकान, बच्चों के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, हॉस्पिटल आदि का निर्माण किया जा चुका है। उन्हें शासन की प्रत्येक योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। पहले मुसहर, कोल, थारू, गोंड, चेरो आदि समुदायों के लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नट, बंजारा, बावरिया, शासी, कंजर, कालबेलिया, सपेरा, जोगी आदि वंचित जनजातियों को जमीन के पट्टे, आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए घुमन्तु जनजाति बोर्ड का निर्माण करने की आवश्यकता है। इन्हें सरकारी नौकरियों तथा शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर वाराणसी जिला प्रशासन ने तत्परता के साथ सुश्री शैला खानम उर्फ निखत परवीन को उनकी मांग के अनुरूप सिलाई मशीन उपलब्ध करायी

सुश्री शैला खानम ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया

लखनऊ : (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आज वाराणसी जिला प्रशासन ने तत्परता के साथ सुश्री शैला खानम उर्फ निखत परवीन को उनकी मांग के अनुरूप सिलाई मशीन उपलब्ध करायी। सिलाई मशीन प्राप्त होने पर सुश्री शैला खानम ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी ने आज सर्किट हाउस सभागार, वाराणसी में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं और समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर सुश्री शैला खानम ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि उनके पास जॉब न होने से उन्हें परेशानी होती है। उनके पति की भी इनकम कम है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से एक सिलाई मशीन की मांग करते हुए कहा कि इसे वह अपनी आजीविका का साधन बनाकर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सिलाई मशीन शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का भरोसा देते हुए जिला प्रशासन को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुश्री शैला खानम को महज 02 घण्टे के अन्दर सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी।

सलमान लाला कौन था? 28 साल की उम्र में 32 , 'गुनाहों का बादशाह', बना कानून का सिरदर्द! चकमा देने में ऐसे मौत

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर 'कुख्यात बादशाह' सलमान लाला उर्फ शाहनवाज अपनी ही चालाकी से मौत का शिकार हुआ। 31 अगस्त 2025 को सीहोर के इंदौर-भोपाल हाईवे पर एक पानी भरे तालाब में उसकी लाश तैरती मिली। 28 साल की उम्र में 32 गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड बनाने वाला सलमान पुलिस के लिए सिरदर्द था।

हत्या, अपहरण, दुष्कर्म, और NDPS जैसे केसों में वॉन्टेड सलमान ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश में तालाब में छलांग लगाई, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से डूब गया। आइए, सलमान लाला की काली दुनिया का हिसाब देखते हैं...

सलमान लाला उर्फ शाहनवाज, इंदौर के नया बसेरा का रहने वाला था। 2012 में मात्र 15 साल की उम्र में उसका पहला केस अपहरण और दुष्कर्म का दर्ज हुआ। इसके बाद उसने हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, अवैध वसूली, और ठऊढर जैसे 32 से ज्यादा अपराध किए।

गैंग का सरगनाः सलमान ने अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब, अरुण मालवीय (डार्लिंग), सौरभ राठौड़, और कुलदीप साल्दे जैसे गुर्गों के साथ इंदौर में आतंक मचाया। वह संभ्रांत परिवारों के युवाओं को भी क्राइम की दुनिया में धकेलता था।

पुलिस का दुश्मनः सलमान

इतना शातिर था कि वह फोन का इस्तेमाल कम करता था और सोशल मीडिया के जरिए अपने गुर्गों से संपर्क रखता था। उसने टक्क्र थाने को बम से उड़ाने की धमकी तक दी थी।

आखिरी चकमा और मौत का तालाब

29-30 अगस्त 2025 की रात इंदौर क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि सलमान लाला अपने भाई सिद्धू (जमानत पर रिहा) को सागर जेल से लेने गया है। क्राइम ब्रांच ने सीहोर बायपास पर उनकी स्कॉर्पियो को घेर लिया। सलमान और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने सिद्धू, अरुण मालवीय, सौरभ, और कुलदीप को दो पिस्टल और जिंदा कारतूसों के साथ दबोच लिया।

सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर भागा और पास के तालाब में छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वह पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन तालाब की गहराई का अंदाजा न होने से वह डूब गया। 31 अगस्त को ग्रामीणों ने तालाब में उसकी लाश देखी। रऊफ़क्र ने शव निकाला, जिसके हाथ में हथकड़ी जैसी चीज थी। एडिशनल ऊढ राजेश दंडोतिया ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का सटीक कारण पता चलेगा।

सलमान लाला का क्राइम रिकॉर्डः 32 गुनाहों की दास्तान

पहला अपराध (2012): 15 साल की उम्र में अपहरण और दुष्कर्म का केस।

गंभीर अपराधः हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, ठऊढर, अवैध वसूली, और डकैती की योजना। टक्क्र, खजराना, और विजय नगर थानों में कई केस दर्ज।

हाई-प्रोफाइल वारदातेंः

2022, ट हॉस्पिटल गोलीकांडः सलमान और उसके गुर्गों ने एम्बुलेंस ड्राइवर विवाद में सद्दाम नामक युवक पर गोलियां चलाईं।

2023, क्रिकेट विवाद हत्याः कबूतरखाना में क्रिकेट खेलने के विवाद में रियाज उर्फ शानू की हत्या। सलमान के गैंग पर ऋक्फ़ दो गिरफ्तार।

2022, इवेंट मैनेजर मर्डरः गाड़ी टकराने के विवाद में सलमान के भाई गोलू और सिद्धू ने तुषार संगर की हत्या की।

पुलिस रडार परः सलमान पर 60,000 रुपये का इनाम था। वह उज्जैन, गुजरात, और राजस्थान में फरार था।

पुलिस का ऑपरेशन और सलमान का अंत

सलमान की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच ने कई राज्यों में दबिश दी। 2024 में उसे पिस्टल के साथ पकड़ा गया, जब उसने पुलिस पर ही हथियार तान दिया। 2022 में इंदौर पुलिस ने सलमान का जुलूस निकाला, जहाँ उसे "अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है" बुलवाया गया।

'रामायण' फेम रामानंद के बेटे प्रेम सागर का निधन, टीवी के राम-लक्ष्मण ने जताया शोक , पढ़ें सफरनामा

(जीएनएस)।

एक दुखद खबर सिनेजगत से है, 'रामायण' बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का आज 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वो वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित थे, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम सागर ने आज सुबह10 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म और टेलीविजन जगत में शोक की लहर है।

प्रेम सागर ने भारतीय मनोरंजन उद्योग में सागर परिवार की विरासत को एक मे्च्योर निमार्ता और कुशल दृश्य तकनीशियन के रूप में आगे बढ़ाया, उनते चाहने वाले उन्हें मृदभाषी और टैलेटंड व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं।

आपको बता दें कि प्रेम सागर पुणे के एफटीआईआई (1968 बैच) के पूर्व छात्र थे, जहां उन्होंने फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफी के गुर सीखे थे। टेलीविजन के लिए कई प्रतिष्ठित शो निर्माण करने के अलावा, उन्होंने कई फिल्मों के लिए सिनेमैटोग्राफर के रूप में भी काम किया था और यही नहीं उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया था, हालांकि उन्हें आशा के अनुरूप इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली थी।

'अन एपिक लाइक ऑफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण'

उनकी लेखन में भी रूचि थी, उन्होंने 'अन एपिक लाइक ऑफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण' नामकिताब भी लिखी थी, जो कि उनके पिता के जीवन पर आधारित थी।

रामानंद सागर के पुत्र होने के नाते प्रेम सागर ने उन्हें प्रतिष्ठित टीवी श्रृंखला 'रामायण' में अपने पिता असिस्ट किया था, उन्होंने 'विक्रम और बेताल' और 'श्री कृष्णा' जैसे टेलीविजन शो के निर्माण में भी अहम रोल प्ले किया था और इसके साथ-साथ उन्होंने 'ललकार', 'आंखें' और धर्मेंद्र- हेमा मालिनी अभिनीत 'चरस' जैसी फिल्मों में बतौर सिनेमैटोग्राफर काम किया था। प्रेम सागर ने जितेंद्र और हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म 'हम तेरे आशिक हैं' का निर्देशन भी किया था।

'रामायण' के राम ने जताया शोक

प्रेम सागर के निधन पर रामानंद सागर की 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर और एमपी अरुण गोविल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है कि 'रामायण टीवी सीरियल का स्वरूप देकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन-जन तक भगवान श्रीराम की मयार्दा, आदर्श और शिक्षाओं को पहुंचाने वाले स्व. श्री रामानंद सागर जी के सुपुत्र एवं प्रसिद्ध फिल्म निमार्ता श्री प्रेम सागर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवारजनों को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।'

'रामायण' के लक्ष्मण ने जताया दुख

तो वहीं ' रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'रामानंद सागर जी के पुत्र प्रेम सागर जी के निधन की खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है। ओम शांति

मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का पीएम? सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे, नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल देश के ही नहीं बल्कि विश्व के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं, भारत के लगातार तीसरी बार पीएम बने मोदी की छवि बेबाक, निडर और स्पष्ट वक्ता की है। हाल ही में आए इंडिया टुडे और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (टडळठ) सर्वे ने एक बार फिर से साबित किया है कि आज भी 'मोदी मैजिक' कम नहीं हुआ है।

लेकिन पीएम मोदी के बाद कौन देश का पीएम बन सकता है? आखिर भाजपा में ऐसा कौन है, जो कि पीएम मोदी की जगह ले सकता है? साल 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा?

ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा है, इसी के मद्देनजर वढवङ ने एक सर्वे किया,जिसमें उसने जनता से सीधे प्रश्न किया कि -मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है?

जिसके लिए उसने तीन विकल्प दिए थे।

इस सर्वे में लोगों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया, आपको बता दें कि सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस रेस में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे हैं, 84 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मोदी के बाद पीएम की कुर्सी के लिए बेस्ट माना है। सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में विख्यात सीएम योगी को लोग पीएम मोदी का उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं।

गृहमंत्री अमित शाह इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, 12 प्रतिशत लोगों को लगता है कि पीएम की कुर्सी के लिए वो मोदी के बाद बेस्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ कहे जाने वाले शाह की पार्टी पर मजबूत पकड़ है, जिन पर जनता को भरोसा है।

तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 4 प्रतिशत लोगों ने पीएम पद के लिए बेस्ट माना है। उनकी स्वच्छ छवि और कार्यप्रणाली उन्हें अलग पहचान देती है लेकिन इस सूची में वे शीर्ष दो नामों से पीछे हैं।

हालांकि दिलचस्प बात ये है कि 52 प्रतिशत लोगों को अभी भी लगता है कि पीएम मोदी को ही फिर से पीएम बनने चाहिए। गौरतलब है कि यह सर्वे 1 जुलाई 2025 से 14 अगस्त 2025 के बीच किया गया था।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक गणेश महोत्सव में सहभागी हुए

मुख्यमंत्री ने बोडकदेव वॉर्ड में 'बोडकदेव का राजा' तथा 'वस्त्रापुर गणेश पंडाल' पहुँच कर बाप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया

गांधीनगर, 31 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया के बोडकदेव वॉर्ड में रविवार को सार्वजनिक गणेश महोत्सव में सहभागी हुए।

समग्र राज्य में जब उमंग एवं उल्लासपूर्वक गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, तब मुख्यमंत्री भी अहमदाबाद शहर में विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक गणेश उत्सव में लोगों के आनंद-उमंग में सहभागी हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने रविवार शाम ह्यबोडकदेव का राजाह्न तथा

ह्यवस्त्रापुर गणेश पंडालह्न पहुँच कर बाप्पा का आशीर्वाद प्राप्त किया।

उन्होंने श्रीजी की भक्तिभावपूर्वक पूजा का लाभ उठाकर धन्यता की अनुभूति की।

वस्त्रापुर तालाब तथा जजेज बंगलॉ चौराहे के पास नगरजनों ने मुख्यमंत्री का अनूठे उत्साह के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी गणेश महोत्सव में उपस्थित रहे नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया तथा नन्हें बच्चों एवं युवाओं के साथ वातार्लाप भी किया।

मुख्यमंत्री ने दोनों स्थानों पर गणेश पंडाल की थीम, श्रीजी के वस्त्राभूषण-श्रृंगार सज्जा तथा गणेश स्थापना के आयोजन की प्रशंसा की।

इस अवसर पर अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी तथा सामाजिक-राजनीतिक अग्रणी उपस्थित रहे।

रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण

केन्द्रीय रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया

लखनऊ : 30 अगस्त, 2025

भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा स्थापित की गई यह इकाई देश की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई है। उन्होंने कम्पनी के सीईओ एवं चेयरमैन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्वरूप अब नोएडा में भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में नोएडा देश की प्रगति में और अधिक सशक्त भूमिका निभाएगा। यह कम्पनी वर्ष 2017 में मात्र 10 सदस्यों से शुरू हुई थी और आज 600 से अधिक युवा इंजीनियर इसमें कार्यरत हैं। आने वाले समय में यह इकाई 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।

रक्षा मंत्री जी ने कहा कि एक समय था, जब उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति

कमजोर थी तथा कानून व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नए युग की ओर कदम बढ़ाया है और आज कानून व्यवस्था की नई पहचान के साथ उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा प्रदेश बन गया है।

रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आज की परिस्थितियों में ड्रोन को युद्ध नीति में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। देश का भविष्य नवाचार के हाथों में है। भारत ने मेडिकल, कृषि और आई0टी0 क्षेत्र में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में रेफी एम फाईबर और डी0आर0डी0ओ0 द्वारा निर्मित तीन उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।

सितंबर में भी खूब बरसेंगे बादल, जानें मौसम विभाग ने किन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

(जीएनएस)।

देश के अधिकांश हिस्सों में अगस्त महीने में मूसलाधार बारिश ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप अगस्त की बारिश से परेशान हैं, तो अभी तैयार रहें। भारतीय मौसम विभाग (क्टऊ) का कहना है कि सितंबर में भी लोगों को मानसूनी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सामान्यतया सितंबर के मध्य तक मॉनसून की वापसी शुरू हो जाती है। आईएमडी का अनुमान है कि इस बार ऐसा कोई संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कुछ राज्यों में सितंबर में भी भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त 2025 में उत्तर पश्चिम भारत में 265 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले 25 साल में हुई सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इसके अलावा, साल 1901 के बाद यानी 125 सालों में यह 13वीं बार है जब इतनी बारिश दर्ज की गई है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगस्त का दूसरा पखवाड़ा जलप्रलय

जैसा साबित हुआ है। पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।

सितंबर में भी एक्टिव रहेगा मॉनसून

मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया कि सितंबर में भी बारिश का औसत सामान्य से करीब 109% तक अधिक हो सकता है। देश के बड़े हिस्से में सितंबर भी बरखा का खेल जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि अमूमन 1 सितंबर को राजस्थान से मॉनसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल यह काफी देर से होगा। मानसून की वापसी की संभावित तारीख 17 सितंबर मानी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सितंबर के महीने में भी अच्छी-खासी वर्षा हो सकती है।

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में अब कैसे हैं हालात? केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ पर दिया अपडेट, खतरनाक स्तर पर पहुंची चेनाब नदी

अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट

31 अगस्त से 3 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो सकती है और इससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

पश्चिमी हिस्सों की बात करें, तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी अगले सात दिनों तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 4 से 6 सितंबर के बीच गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वोत्तर के इलाकों में इस साल अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है। सितंबर में भी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में इस दौरान अपेक्षाकृत कम बारिश होने की संभावना है।

अचानक अशोक चौधरी के दिल्ली स्थित घर पहुंचे नीतीश कुमार, बिहार में पक रही है बड़ी सियासी खिचड़ी?

(जीएनएस)।

चुनाव के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, प्रदेश का सियासी पारा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अब रविवार को अचानक वह अशोक चौधरी के घर पहुंचे। चौधरी के घर पर ही नीतीश की मुलाकात अनंत सिंह से भी हुई है। राजनीतिक गहमा-गहमी के समय में यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं ने हंसते-मुस्कुराते कुछ देर तक बात की और फिर चले गए।

विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग आने वाले दिनों में कई सारी होने की उम्मीद है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही यह चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन और वोट चोरी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन आक्रामक हमले कर रहे हैं और राज्य में एक बार फिर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिख रही है।

नीतीश कुमार के अचानक अशोक चौधरी के घर पहुंचने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात के पीछे क्या उद्देश्य है, अब तक इसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के पीछे आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ राजनीतिक चर्चा हुई है। इसके अलावा, बताया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में नीतीश बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी बैठक करने वाले हैं और दिल्ली का दौरा भी सितंबर में मुमकिन है।

जेल से छूटने के बाद ही अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह मोकामा से चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं और लगातार चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा, यह भी कहा जा रहा है कि अनंत को टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी के अदंर ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अनंत सिंह और नीतीश की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच की सहजता देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि बाहुबली नेता को मोकामा से टिकट मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।

बिहार : अकेले ही लड़ेगी बसपा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ो भतीजे आकाश आनंद को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

(जीएनएस)।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी की अहम बैठक के बाद ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव के लिए किसी दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की अब तक कोई उत्सुकता नहीं दिखाई गई है और उम्मीद के मुताबिक उन्होंने अकेले ही चुनावी संग्राम में उतरने का फैसला किया है।

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि दो दिनों की

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद हमने यह फैसला किया है और अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि अगले महीने से चुनाव सभाएं भी आयोजित की जाएंगी।

सोशल साइस एक्स पर एक पोस्ट में, मायावती ने लिखा कि वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उम्मीदवारों के चयन और अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनावों की समग्र तैयारियों पर चर्चा हुई है। बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि अगले महीने की शुरूआत में शुरू होने वाली पार्टी यात्राओं और जनसभाओं जैसे कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं और पार्टी की रैलियों समेत संगठन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है।

बिहार में मायावती की पार्टी का कोई ठोस कैडर नहीं है और चुनावी नतीजों पर इसका बड़ा असर देखने की संभावना कम ही मानी जा रही है। हालांकि, विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही पार्टी की असल ताकत के बारे में कहा जा सकता है।

'फोटो सेशन नहीं, भारतीयों को इन मुद्दों पर जवाब चाहिए', मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी ने पूछे ये अहम सवाल

(जीएनएस)।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बैठक को 'फोटो सेशन' करार देते हुए सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जाहिर की।

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा कि देश जिन अहम मुद्दों पर जवाब की उम्मीद कर रहा था, उन पर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने चीन के पाकिस्तान को समर्थन, CPEC (चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर) के विस्तार और सीमा विवाद जैसे मामलों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।

ओवैसी ने विशेष रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन और उढएउ के अफगानिस्तान तक विस्तार

को लेकर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।

उन्होंने चीन द्वारा नदी जल संबंधी आंकड़े साझा न करने और लद्दाख में सीमा पर भारतीय सैनिकों को अभी भी बफर जोन में गश्त न करने देने का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि 2020 से भारतीय पशुपालकों को भी कई इलाकों में जाने से रोका जा रहा है, जिस पर कोई प्रगति नहीं हुई।

ओवैसी ने आगे कहा कि चीन ने न तो भारत को रेयर अर्थ मटेरियल और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति फिर से शुरू करने का कोई आश्वासन दिया और न ही भारत से आयात बढ़ाने की कोई बात कही। उन्होंने इन सभी को भारतीय जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बताया।

ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बैठक पर तंज कसते हुए कहा, "ये सभी भारतीयों के मुद्दे थे। न कि फोटो सेशन करवाना या जैकेट का रंग या कालीन की लंबाई। दुर्भाग्य से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात सार्थक मुद्दों पर विफल रही।"

गौरतलब है कि रउड शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की थी। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान और विश्वास की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसे भारत-चीन संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया।

डिजिटल इंडिया की उपलब्धि: एनईजीडी ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर लगभग 2,000 ई-सरकारी सेवाओं का अखिल भारतीय एकीकरण अर्जित किया

सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक अब कहीं भी, कभी भी प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाओं, सुविधा केन् द्र भुगतानों और अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं

महाराष्ट्र 254 सेवाएं प्रदान करके देश में अग्रणी है, जो नागरिकों के लिए उपलब्ध डिजिटल सेवाओं की सबसे अधिक संख्या है, इसके बाद दिल्ली 123, कर्नाटक 113, असम 102 और 86 सेवाओं के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है

(जीएनएस)।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस सेवाओं के अखिल भारतीय समेकन को सक्षम बनाने के जरिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। इस उपलब्धि के साथ, सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक अब कहीं भी, कभी भी लगभग 2,000 डिजिटल सेवाओं का निर्बाध उपयोग कर सकते हैं।

एकीकृत सेवाएं प्रमाणपत्र, कल्याणकारी योजनाओं, सुविधा केन् द्र भुगतानों और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित नागरिकों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिससे वितरण में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह प्रगति डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विजन को साकार करने, कागज रहित और गतिशील शासन को बढ़ावा देने तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में प्रत्यक्ष योगदान देने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

डिजिलॉकर अंतर-संचालनीयता, डेटा सुरक्षा और बहु-हितधारक समन्वय की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करने के माध् यम से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरा है। इसके नवोन्मेषी और सुदृढ़ ढांचे ने पहुंच में सुगमता, समावेशिता और विश्वसनीयता को संभव बनाया है और देश भर के नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं से सशक्त बनाया है।

इस विस्तार के साथ, महाराष्ट्र में नागरिकों को अब सबसे अधिक 254 सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हुई है, उसके बाद दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक् त, केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 77 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश 76 और गुजरात 64 सेवाएं प्रदान करता है। इसी प्रकार, तमिलनाडु और गोवा प्रत्येक 63 सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि हरियाणा 60 और हिमाचल प्रदेश 58 सेवाएं प्रदान करता है। कुल मिलाकर, वर्तमान में देश भर में नागरिकों के लिए 1,938 सेवाएं उपलब्ध हैं।

इस सफलता के आधार पर, एनईजीडी की योजना एआई-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ई-सरकारी सेवाओं के पोर्टफोलियो का और विस्तार करने की है। राज्य स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, साथ ही निरंतर नवोन् मेषण से अधिक समावेशिता और सेवाओं की बेहतर तथा समग्र पहुंच सुनिश्चित होगी।

यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी भारत के विजन के अनुरूप नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

एनईजीडी के बारे में

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2009 में डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (एक गैर-लाभकारी संस्था), जो धारा 8 के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग की स्थापना की। 2009 से, एनईजीडी, कार्यक्रम प्रबंधन और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य सरकारी संगठनों को तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान करता है।

एनईजीडी के महत् वपूर्ण प्रचालनगत क्षेत्रों में प्रमुख डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन, परियोजना विकास, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जागरूकता और संचार संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। एनईजीडी ने डिजिलॉकर, एंटिटी लॉकर, उमंग, ओपनफोर्ज, एपीआई सेतु, मायस्कीम, इंडिया स्टैक ग्लोबल, मेरी पहचान, यूएक् स4जी आदि जैसे कई राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित और प्रबंधित किए हैं।

घर में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत और कई के मलबे में दबे होने की आशंका

(जीएनएस)।

लखनऊ में घर के अंदर पटाखा फैक्ट्री चलाने का एक मामला सामने आया है। डंबा क्षेत्र के बेहटा गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में चार लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये चारों लोग एक ही परिवार के हैं। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है और रेस्क्यू चलाया जा रहा है। विस्फोट रविवार की सुबह हुआ जिसके बाद आसपास के लोगों को घर के अंदर ही पटाखा फैक्ट्री चलाने की जानकारी हुई। बता दें कि घर के अंदर विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों को बनाने पर सख्त पाबंदी है।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। इस हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया

है और अधिकारियों को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग ही मिलकर घर में पटाखा बनाने का काम करते थे।

इस हादसे में मृतकों की पहचान पटाखा व्यवसायी आलम, आलम की पत्नी और आलम के दो बेटे के रूप में हुई है। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से आसपास पूरे इलाके में मातम पसर गया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, मलबे में से लोगों को निकालने का काम जारी है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है।

स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घर में पटाखा फैक्ट्री चलाने के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले भी एकाध बार छोटे-मोटे धमाकों की आवाज सुनी थी। इसके बाद सुरक्षा को लेकर हमने अपनी शंका जाहिर की थी। पुलिस जांच टीम ने कहा कि फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके बाद आगे की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी।